(iii) speedier economic development of the State.

(iv) continued efforts to bring the insurgent groups to the discussion table.

पुलिस आयोग की सिफारिशें

2314. **प्रो0 विजय कुमार मल्होत्रा** : क्या **गृह** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार को कब प्रस्तुत की;

(ख) सरकार और राज्य-सरकारों ने कौन-कौन सी सिफारिशे स्वीकार की है; उनका राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार के विचार में कौन-कौन सी सिफारिशें राज्य सरकारों को स्वीकार करनी चाहिए?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी) : (क) से (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1979 से 1981 तक के दौरान 8 रिपोर्ट प्रस्तुत की। पहली रिपोर्ट पर नई दिल्ली में जून, 1979 में आयोजित मुख्य मंत्रियों के सम्मेलन में विचार किया गया था 01.2.1980 को उसे सदन के पटल पर रखा गया था। आयोग की अन्य रिपोर्ट भी सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों को उनके विचारार्थ तथा उचित कार्रवाई हेतु भेजी गई थी, जिन्हें 30.3.1983 को सदन के पटल पर रख दिया गया था।

2. चूंकि "पुलिस" राज्य का विषय है, अतः राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों को कार्यान्वयन करना मुख्य रूप से राज्य सरकारों का कार्य है। इन सिफारिशों का शीघ्रता से कार्यान्वयन सुनिश्चित करने हेतु केन्द्र सरकार उनसे अनुरोध करती आ रही है। राज्यों से प्राप्त जवाबों से पता चलता है कि उन्होंने रिपोर्टो पर विचार किया है तथा उनके द्वारा उचित समझी गई अनेक सिफारिशों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से कार्रवाई की गई है।

3. इन रिपोर्टो में केन्द्र सरकार से संबंधित सिफारिशों की भी पहचान की गई है। मंजूर की गई सिफारिशों पर भी कार्रवाई की गई है। कुछ मुद्दों, विशेष रूप से वे जिन्में मौजूदा कानूनों में संशोधन करना अपेक्षित है, कार्यान्वयन की विभिन्न अवस्थाओं में है।

4. 6.5.98 को जारी उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अनुसर्ण में, 25.5.98 को श्री जे0एफ0 रिबैरों की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है जो राष्ट्रीय पुलिस आयोग की सिफारिशों की पुनरीक्षा करेगी तथा लम्बित पडी सिफारिशों के कार्यान्वयन हेतु और तौर-तरीके सुझाएगी

Additional Forces for Tripura

2315. SHRI KHAGEN DAS: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government of Tripura have requested his Ministry for deployment of additional forces in the State in view of the activities of the extremist groups;

(b) if so, whether Government are sending additional forces to the State; and

(c) by when, the additional forces will reach the State?

THE MINISTER OF HOME AFFAIRS (SHRI L.K. ADVANI): (a) Yes, Sir.

(b) and (c) Central Para Military Forces have been made available to Government of Tripura. The deployment of security forces depends upon their availability and the overall security scenario.

Witness Languishes in Jail

2316. SHRI O.P. KOHLI Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) whether Government's attention has been drawn to the news-item captioned "Witness spends 10 years in custody; case yet to begin" appearing in the Times of India, dated 7th May, 1998;

(b) if so, the facts thereof and the reaction of Government -thereto;

(c) what steps Government propose to take to ensure that such incidents do not take place in future anywhere in the